शीला बी. दास

बनाम

पी. आर. सुगेसरी

17 फरवरी, 2006

[बी. पी. सिंह और अल्टमास कबीर, जे. जे.]

अभिभावक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890; धारा 7 और 25-हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956; धारा 6-तलाक के बाद पिता और माता द्वारा बच्चे की अभिरक्षा का दावा-बच्चे ने अपने पिता के परिवार के साथ रहना पसंद किया- बच्चे की इच्छा को ध्यान में रखते हुए पारिवारिक न्यायालय द्वारा पिता के पक्ष में निर्णय किया गया- उच्च न्यायालय ने माता की याचिका अस्वीकार की- तथ्यों के आधार पर निर्णय दिया कि अपने पिता के साथ खुश है इसलिए, बच्चे के हित की सबसे अच्छी सेवा तब होगी जब वह अपने पिता के साथ रहती है, लेकिन अदालत के निर्देश के अनुसार माँ को लगातार अंतराल पर अपने बच्चे से मिलने के लिए पर्याप्त पहुंच उपलब्ध है।

अपीलार्थी-डॉक्टर और प्रत्यर्थी-वकील ने विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के तहत शादी की और उनके एक लड़की का जन्म हुआ। अपीलार्थी प्रत्यर्थी को सूचित किए बिना बच्चे के साथ अपना वैवाहिक घर छोड़ चली गई। प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण की एक रिट दायर की जिसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक वचन पर निस्तारित किया गया कि अपीलार्थी बच्चे को उसके वैवाहिक घर वापस जाने देगी। इसके बाद, प्रत्यर्थी ने अभिभावक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 7 और 25 के तहत और हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6 के तहत परिवार न्यायालय के समक्ष दो आवेदन दायर किए। प्रत्यर्थी

ने नाबालिग बच्चे की अंतरिम अभिरक्षा के लिए परिवार न्यायालय के समक्ष एक आवेदन भी दायर किया। बच्चे की अंतरिम अभिरक्षा के लिए प्रत्यर्थी की प्रार्थना के संबंध में अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए नाबालिग बच्चे का साक्षात्कार करने के बाद, परिवार न्यायालय ने कुछ निर्देश देकर प्रत्यर्थी के दो आवेदनों को अनुमति दी और अपीलार्थी को बच्चे की अभिरक्षा प्रत्यर्थी को देने का निर्देश दिया।

अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की जिसमें परिवार न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी गई। प्रत्यर्थी ने स्थगन के आदेश की समीक्षा के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया। उच्च न्यायालय ने परिवार न्यायालय को नाबालिग बच्चे से पूछताछ करने का निर्देश दिया। परिवार न्यायालय द्वारा नाबालिग बच्चे का साक्षात्कार लिया और उच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट दी जिसमें कहा गया कि नाबालिग बच्चे ने प्रत्यर्थी के साथ रहना पसंद किया है। उच्च न्यायालय ने अंतरिम रोक को हटा दिया और अपील के निपटारे तक प्रत्यर्थी को नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा प्रदान कर दी। इसके बाद प्रत्यर्थी ने पारिवारिक न्यायालय में तलाक के लिए आवेदन दायर किया। अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के प्रत्यर्थी को नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा देने के आदेश जो खारिज किया गया था उसके खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की। इसके बाद उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी। इसके तुरंत बाद परिवार न्यायालय ने दोनों पक्षों को तलाक देने की मंजूरी दे दी।

अदालत में अपील में, अपीलार्थी-माँ ने तर्क दिया कि नाबालिग बच्चा कम उम्र का था और जल्द ही यौवन प्राप्त कर लेगा जब उसे एक महिला के मार्गदर्शन और निर्देशों की आवश्यकता होगी ताकि वह ऐसी अवधि के दौरान होने वाले शारीरिक और भावनात्मक दोनों परिवर्तनों से निपटने में सक्षम हो सके; उसके एक डॉक्टर होने के नाते, नाबालिग बच्चे की जरूरतों का ध्यान रखने के लिए प्रत्यर्थी की तुलना में बेहतर स्थिति में होगी, जिसके पास नाबालिग बच्चे की जरूरतों की देखभाल करने के लिए

बहुत कम समय था; कि नाबालिग बच्चा उससे तब तक बेहद खुश था जब तक कि प्रत्यर्थी-पिता ने बच्चे की अभिरक्षा का दावा करना शुरू नहीं किया और अभिरक्षा प्राप्त करने के तुरंत बाद, प्रत्यर्थी ने अपने बच्चे को परिवार न्यायालय को यह बताने के लिए प्रभावित किया कि वह अपने पिता के साथ रहना पसंद करती है; कि बच्चे को प्रत्यर्थी द्वारा "पेरेंटल एलियनशन सिंड्रोम" के संपर्क में लाया गया है और इसलिए कि उसने नाबालिग बच्चे के लाभ के लिए विभिन्न वित्तीय निवेश किए; कि, हालांकि उसे इस अदालत के एक अंतरिम आदेश द्वारा मिलने का अधिकार दिया गया था, वह दूरी के कारण उसके संपर्क में रहने में असमर्थ थी और प्रत्यर्थी ने उसे कभी भी नाबालिग बच्चे से मिलने और उसके साथ पर्याप्त समय बिताने की अनुमति नहीं दी।

प्रत्यर्थी-पिता ने अपीलार्थी के विभिन्न आरोपों से इनकार करते हुए तर्क दिया कि नाबालिग बच्चे को अपीलार्थी द्वारा अचानक और गुप्त रूप से उसकी अभिरक्षा से हटा दिया गया था, जिसने अपीलार्थी को सूचित किए बिना अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया था; कि नाबालिग बच्चे ने परिवार न्यायालय के समक्ष अपने पिता के साथ रहने को प्राथमिकता दी, भले ही अपीलार्थी ने नाबालिग बच्चे को प्रत्यर्थी से जबरन हटा दिया हो; कि उसने अपनी बड़ी बहन के साथ अपने नाबालिग बच्चे की जरूरतों की देखभाल करने के लिए व्यवस्था की जिस पर परिवार न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा विधिवत विचार किया गया था; और यह कि उसके पास नाबालिग बच्चे की सभी जरूरतों की देखभाल करने और उन्हें पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्त था। प्रत्यर्थी ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी का नाबालिग बच्चे से मिलने के लिए या तो प्रत्यर्थी के घर या किसी अन्य स्थान पर स्वागत है और यदि बच्चा अपीलार्थी के साथ रहने के लिए तैयार है तो कुछ चुनिंदा दिनों के लिए अपीलार्थी उसे अपने साथ रख सकती है।

इस न्यायालय द्वारा-पारिवारिक न्यायालय के आदेश में कुछ संशोधनों के साथ अपील का निपटान किया गया।

अभिनिर्धारित किया गया- 12 वर्ष से कुछ अधिक उम्र की बच्ची अत्यधिक बुद्धिमान है, उसने स्कूल में अपनी पढ़ाई में लगातार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और हमें विश्वास था कि उसके माता-पिता के बीच झगड़े के बावजूद, वह एक बुद्धिमान विकल्प चुनने की स्थिति में होगी। उसकी अभिरक्षा के संबंध में नाबालिग के साथ हमारी चर्चा से, हम यह समझने में सक्षम हुए हैं कि यद्यपि उसकी अपनी माँ के प्रति कोई शत्रुता नहीं है, फिर भी वह उस पिता के साथ रहना पसंद करेगी जिसके साथ वह अधिक सहज महसूस करती है। नाबालिग बच्ची ने हमें यह भी बताया कि उसने अपनी मौसी के साथ बहुत अच्छे संबंध स्थापित कर लिए हैं, जो अब उसके पिता के घर में रह रही थी और वह अपनी मौसी से उन मामलों में भी संबंध बनाने में सक्षम थी जो किशोरावस्था के दौरान एक बढ़ती लड़की के लिए चिंता का विषय हो सकते थे।

प्रत्यर्थी को नाबालिग की देखभाल के लिए अयोग्य मानने का कोई कारण नहीं है। वास्तव में, नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा प्राप्त करने के बाद, प्रत्यर्थी ने नाबालिग की जरूरतों आैर देखभाल में उपेक्षा नहीं की है। बच्चा उत्तरदाता की संगति में खुश प्रतीत होता है और स्कूल में भी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। प्रत्यर्थी आर्थिक रूप से स्थिर प्रतीत होता है और किसी भी तरह से नाबालिग बच्चे का अभिभावक होने के लिए अयोग्य भी नहीं है। नाबालिग के प्रति उसकी कथित उदासीनता की तुलना में जो आरोप अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के खिलाफ लगाया गया है। उसके अलावा अन्य कोई आरोप नहीं है। किसी सामग्री से इस तरह के आरोप की पुष्टि नहीं होती है और प्रत्यर्थी को नाबालिग के अभिभावक के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य बनाने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। अतः यह न्यायालय महसूस करता है कि नाबालिग के हित में सबसे अच्छा तब होगा जब वह प्रत्यर्थी के साथ रहती है, लेकिन अपीलार्थी के पास पर्याप्त पहुंच होगी कि वह नाबालिग के साथ लगातार अंतराल पर नाबालिग से मिलने जाती रहे, परंतु उसकी सामान्य पढ़ाई और अन्य गतिविधियों में बाधा न आए।

संदर्भित-होशी शावक्षा डोलिकुका बनाम तीस होशी डोलिकुका, एआईआर (1984) एससी 410; कुमार बनाम जहांगीरदार बनाम चेतना रामतीर्थ, [2004] 2 एस. सी. सी. 688 और रोजी जैकब बनाम जैकब ए चक्रमक्कल, ए. आई. आर. (1973) एस. सी. 2090, कुरियन सी. जोस बनाम मीना जोस (1992) 1 के. एल. टी. 818 और सरस्वतीबाई श्रीपद वेद बनाम श्रीपद वसंजी वेद, एआईआर (1941) बॉम्बे 103 का उल्लेख किया गया है।

सिविल अपीलीय न्याय निर्णयः सिविल अपील सं. 6626/2004

उच्च न्यायालय, केरल के एम. एफ. ए. सं. 365/2001 (डी) में दिनांकित 16.06.2003 के निर्णय और आदेश से।

उपस्थिति अपीलार्थी व्यक्तिगत रूप से।

प्रत्यर्थी के लिए एम. पी. विनोद, साजिथ और ए. रघुनाथ।

न्यायालय का निर्णय अल्टमास कबीर, जे. द्वारा दिया गया था।

अपीलकर्ता, जो पेशे से बाल रोग विशेषज्ञ है, का विवाह प्रत्यर्थी, जो पेशे से वकील है, से 29 मार्च, 1989 को विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों के तहत केरल के त्रिशूर में हुआ था। उक्त विवाह से 20 जून 1993 को एक लड़की ऋत्विका का जन्म हुआ।

जैसा कि रिकॉर्ड में मौजूद सामग्रियों से पता चलता है, अपीलकर्ता, किसी भी कारण से, 26 फरवरी, 2000 को बच्चे के साथ त्रिशूर में अपना वैवाहिक घर छोड़कर प्रत्यर्थी को सूचित किए बिना कालीकट चली गई। इसके बाद, यह पता चलने पर कि अपीलकर्ता कालीकट में रह रहा है, प्रत्यर्थी ने बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति की रिट के लिए केरल उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया, जिसका निपटान 24 मार्च,

2000 को किया गया प्रतीत होता है। अपीलकर्ता द्वारा बच्चे को त्रिशूर लाने का वचन दिया गया।

24 मार्च, 2000 को प्रत्यर्थी ने यह आरोप लगाते हुए कि नाबालिग बच्चे को अपीलकर्ता द्वारा गलत तरीके से उसकी अभिरक्षा से हटा दिया गया था, अभिभावक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 7 और 25 के तहत त्रिशूर में परिवार न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया और हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6 भी, जिसे 2000 के ओपी 193 और 2000 के ओपी 239 के रूप में क्रमांकित किया गया।

निपटान के लिए उक्त दो आवेदनों पर विचार करने से पहले, त्रिशूर के पारिवारिक न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने नाबालिग बच्चे की अंतरिम अभिरक्षा के लिए प्रत्यर्थी के आवेदन पर विचार किया और 27 अप्रैल, 2000 को अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए नाबालिग बच्चे का साक्षात्कार लिया। अंतरिम अभिरक्षा के लिए प्रत्यर्थी की प्रार्थना के संबंध में। अंतरिम अभिरक्षा के लिए प्रत्यर्थी के आवेदन पर उस समय कोई आदेश नहीं दिया गया था। 20 मार्च, 2001 को त्रिशूर के पारिवारिक न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम की धारा 7 और 25 और हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम की धारा 6 के तहत प्रत्यर्थी द्वारा दायर दो आवेदनों को अंतिम रूप दिया। निपटान। मामले का निपटारा करते समय विद्वान न्यायाधीश को फैसला सुनाने से पहले एक बार फिर नाबालिग बच्चे से साक्षात्कार करने का अवसर मिला और अंततः त्रिशूर के पारिवारिक न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने 16 तारीख के अपने आदेश से निम्नलिखित आदेश पारित करके प्रत्यर्थी द्वारा दायर आवेदनों को अनुमति दी:

1. प्रत्यर्थी को गर्मी की छुट्टियों के लिए स्कूल बंद होने के तुरंत बाद बच्चे की कस्टडी याचिकाकर्ता, बच्चे के पिता, प्राकृतिक अभिभावक को देने का निर्देश दिया जाता है।

2. पिता सीएसएम सेंट्रल स्कूल एडासेरी में नाबालिग बच्चे की पढ़ाई जारी रखने के लिए कदम उठाएगा और नाबालिग बच्चे को पाठ्येतर गतिविधियों और पढ़ाई का आनंद लेने के लिए सभी सुविधाएं बहाल करने के लिए कदम उठाएगा।

3. प्रत्यर्थी मां याचिकाकर्ता के घर या स्कूल में किसी भी समय बच्चे से मिलने के लिए स्वतंत्र है।

4. यदि प्रत्यर्थी की मां अपना निवास 10 किलोमीटर के भीतर किसी स्थान पर स्थानांतरित कर देती है। जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसके दायरे में बच्चा सप्ताह में कम से कम तीन दिन मां के साथ रह सकता है। याचिकाकर्ता पिता को ऐसी हालत में बच्चे को मां द्वारा अपने घर ले जाने पर आपत्ति नहीं होगी।

5. याचिकाकर्ता पिता को नाबालिग बच्चे की शिक्षा, भोजन और कपड़े आदि के सभी खर्चों को पूरा करना होगा और मां अपनी मर्जी से बच्चे के लिए कुछ भी योगदान देगी और पिता को मां को पैसे देने से रोकना नहीं चाहिए। उसके आराम और सुखद जीवन के लिए कुछ भी बच्चा पैदा करो।

6. यदि प्रत्यर्थी की मां 10 किलोमीटर के भीतर रहने में विफल रहती है। सीएसएम सेंट्रल स्कूल, एडसेरी के दायरे में, हालांकि वह महीने में किसी भी सप्ताहांत में 2 दिन और गर्मी की छुट्टियों के दौरान 10 दिन और ओणम की छुट्टियों के दौरान थिरुवोणम दिवस को छोड़कर 2 दिन के लिए बच्चे की कस्टडी पाने की हकदार है।

7. अभिरक्षा की यह व्यवस्था नाबालिग बच्चे के कल्याण के लिए मुख्य विचार के आधार पर की जाती है और यदि नाबालिग बच्चे के कल्याण को प्रभावित करने

वाली स्थिति या परिस्थिति में कोई बदलाव होता है, तो दोनों पक्ष स्वतंत्र हैं बदली हुई परिस्थिति के आधार पर नए निर्देशों के लिए इस न्यायालय से संपर्क करें ।

ओपी 239/2000 को आंशिक रूप से अनुमति दी गई है जो प्रत्यर्थी प्रति को स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा जबरन हटाने या लेने से रोकता है। "बी" अनुसूची में वर्णित अनुच्छेदों बाबत् दोनों पक्षों ने इन मामलों में अपनी कीमत चुकानी है।

फैमिली कोर्ट के आदेश से असंतुष्ट होकर, अपीलकर्ता ने केरल उच्च न्यायालय में एमएफए नंबर 365/01 के तहत अपील दायर की, जिसमें 21 मई, 2001 के एक आदेश द्वारा फैमिली कोर्ट के आदेश को स्थगित किया गया। इसके बाद प्रत्यर्थी ने उक्त आदेश की समीक्षा के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया और लंबित कार्यवाही में, उच्च न्यायालय द्वारा कालीकट के परिवार न्यायालय को नाबालिग बच्चे का साक्षात्कार करने का निर्देश दिया गया। फैमिली कोर्ट की रिपोर्ट 5 जुलाई, 2001 को उच्च न्यायालय के समक्ष विधिवत दायर की गई थी। उक्त रिपोर्ट से, जिसकी एक प्रति पेपरबुक में शामिल की गई है, यह स्पष्ट है कि नाबालिग बच्ची ने अपने पिता के साथ रहना पसंद किया और अंततः 25 जुलाई, 2001 के अपने आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने 21 मई, 2001 को अपने द्वारा दिये गये स्थगन को हटा दिया।

यहां अपीलकर्ता के आवेदन पर मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करने और प्रस्तुत करने के लिए अपीलकर्ता और प्रत्यर्थी का साक्षात्कार करने के लिए 14 सितंबर, 2001 को उच्च न्यायालय द्वारा मनोचिकित्सक डॉ. एसडी सिंह को भी नियुक्त किया गया था। प्रतिवेदन की ऐसी रिपोर्ट दायर होने पर, उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 31 मई, 2002 द्वारा अपील के निपटान तक प्रत्यर्थी को नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा प्रदान की।

इसके तुरंत बाद, जून 2002 में, प्रत्यर्थी ने त्रिशूर में फैमिली कोर्ट के समक्ष तलाक के लिए एक आवेदन दायर किया। जबकि यह लंबित था, अपीलकर्ता ने अपील के निपटान तक प्रत्यर्थी को नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा देने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एसएलपी (सी) सीसी नंबर 6954/2002 के रूप में एक एसएलपी दायर की। उक्त एसएलपी को 9 सितंबर, 2002 को खारिज कर दिया गया था। संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम की धारा 7 और 25 के तहत प्रत्यर्थी के आवेदन को अनुमति देने वाले परिवार न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपील, एमएफए नंबर 365/01 को भी 16 जून, 2003 को खारिज कर दिया गया। इसके तुरंत बाद, 28 जून, 2003 को फैमिली कोर्ट ने दोनों पक्षों को तलाक दे दिया।

8. अपनी अपील के खारिज होने से व्यथित होकर, एमएफएनंबर 365/01 होने के कारण, अपीलकर्ता ने तत्काल विशेष अनुमति याचिका दायर की, जो एसएलपी नंबर 18961 / 2003 थी, जिसे स्वीकार करने के बाद सिविल अपील नंबर 6626/2004 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया। 20 जुलाई, 2004 को अपीलकर्ता ने अगस्त और सितंबर, 2004 के महीनों के लिए अपने नाबालिग बच्चे के संबंध में अंतरिम मुलाक़ात अधिकारों के लिए लंबित एसएलपी में एक याचिका दायर की। व्यक्ति, और प्रत्यर्थी के विद्वान वकील, इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:

> "यह याचिका लगभग 12 वर्ष की नाबालिग लड़की ऋत्विका की माँ द्वारा दायर की गई है, जिसमें 16 जून, 2003 के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। आक्षेपित आदेश के द्वारा उच्च न्यायालय ने परिवार न्यायालय के आदेश की पुष्टि की है कि यह बच्चे के सर्वोत्तम हित में है कि वह पिता की अभिरक्षा में रहे। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को महीने में एक बार, यानी हर महीने के

पहले रविवार को बच्चे से मिलने उसके पिता के घर जाने और वहाँ बच्चे के साथ पूरा दिन बिताने की अनुमति दी, इस शर्त के साथ कि वह नहीं जाएगी। पिता के घर से निकाल दिया गया। याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी फरवरी, 2000 से एक साथ नहीं रह रहे हैं। उनके बीच तलाक 26 जून, 2003 के आदेश द्वारा हुआ।अंतरिम अभिरक्षा के सवाल पर 30 अप्रैल, 2003 के आदेश के संदर्भ में, फैमिली कोर्ट त्रिचूर को मई, जून और जुलाई, 2004 के महीनों के लिए याचिकाकर्ता के मुलाक़ात अधिकारों के संबंध में एक आदेश देने का निर्देश दिया गया था ताकि याचिकाकर्ता अपनी बेटी से किसी तटस्थ व्यक्ति के स्थान पर और यदि आवश्यक हो, परिवार परामर्शदाता या परिवार न्यायालय द्वारा उचित, उपयुक्त और उचित समझे गए किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में मिल सकती है फैमिली कोर्ट को पक्षों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 2004 के मई, जून और जुलाई के महीनों में कोई दो दिन तय करने का निर्देश दिया गया, जब याचिकाकर्ता अपने बच्चे के साथ पूरा दिन बिताने की स्थिति में हो।"

उपरोक्त आदेश के अनुसरण में फैमिली कोर्ट ने मई, जून और जुलाई, 2004 के महीनों में दो दिन तय किए थे ताकि याचिकाकर्ता उन दिनों अपनी बेटी से मिल सके। फैमिली कोर्ट ने निर्देश दिया कि उक्त बैठक कोर्ट परिसर में फैमिली काउंसलर के कमरे में होगी। याचिकाकर्ता के अनुसार उक्त व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी, यहां तक कि अंततः उसने फैमिली कोर्ट से अनुरोध किया कि उसकी बेटी से फैमिली काउंसलर के कमरे में मिलने के बजाय, उसके पिता के घर पर उससे मिलने की पहले की व्यवस्था को खत्म किया जाए। बहाल

हालांकि पारिवारिक न्यायालय ने 30 अप्रैल, 2004 को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को ध्यान में रखते हुए आदेश में कोई संशोधन नहीं किया। हालाँकि, इस स्तर पर इस पहलू पर और अधिक विस्तार करना आवश्यक नहीं है। ऋत्विका त्रिचूर के एक स्कूल में 7 वीं कक्षा में पढ़ रही है। व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी के विद्वान वकील को सुनने के बाद और रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद, हमारा विचार है कि विशेष अनुमति याचिका में पार्टियों के अधिकारों और तर्कों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, याचिकाकर्ता के महीनों के मुलाक़ात अधिकारों के लिए कुछ अंतरिम आदेश अगस्त और सितंबर, 2004 पारित होने योग्य है। तदनुसार, हम निम्नानुसार निर्देशित करते हैं:

(1) याचिकाकर्ता 1 अगस्त, 2004 से प्रत्येक रविवार को त्रिचूर स्थित प्रत्यर्थी के घर जा सकता है और सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक ऋत्विका के साथ रह सकता है। याचिकाकर्ता के प्रत्यर्थी के घर पर रहने के दौरान, केवल विधवा ही रह सकती है। प्रत्यर्थी की बहन उपस्थित रह सकती है। उक्त अवधि के दौरान प्रत्यर्थी घर में उपस्थित नहीं रहेगा। याचिकाकर्ता ऋत्विका को बाहर ले जाने के लिए स्वतंत्र होगा, बशर्ते कि ऋत्विका इसके लिए तुरंत सहमत हो। हम यह भी आशा करते हैं कि जब प्रत्यर्थी के घर पर, याचिकाकर्ता की उचित देखभाल की जाएगी, जहां तक सामान्य सुविधाओं और शिष्टाचार का सवाल है;

(2) हमें सूचित किया गया है कि जिस स्कूल में ऋत्विका पढ़ रही है वह ओणम त्योहार के दौरान अगस्त, 2004 के महीने में 7 दिनों के लिए बंटाकर्ता का कटियों के दोरान तीन दिनों की अवधि के लिए बच्चे को बाहर ले जाने के लिए खुला होगा। तीन दिन की समाप्ति के बाद बच्चे को प्रत्यर्थी के घर छोड़ने की जिम्मेदारी याचिकाकर्ता की होगी। प्रत्येक रविवार को बैठक की व्यवस्था सितम्बर, 2004 में भी जारी रहेगी। मामले को 5 अक्टूबर, 2004 को सूचीबद्ध किया।

एसएलपी के निर्णय के लंबित रहने तक अपीलकर्ता के मुलाक़ात अधिकारों से सबंधित प्रश्न 5 अक्टूबर, 2004 को इस न्यायालय के समक्ष फिर से विचार के लिए आया, जब 20 जुलाई, 2004 के अपने पहले के आदेश के संदर्भ में, इस न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि अपीलकर्ता एमएफए नं. 365/01 में उचित आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिस पर 16 जून, 2003 को उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया था और उच्च न्यायालय पक्षों या उनके वकील को सुनने के बाद ऐसे आदेश पारित करेगा जैसा वह विचार करेगा। क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान ऋत्विका की अंतरिम अभिरक्षा के संबंध में उपयुक्त। यह भी स्पष्ट किया गया कि जब तक इस न्यायालय द्वारा मामले का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक अपीलकर्ता उच्च न्यायालय के समक्ष इसी तरह के आवेदन करने के लिए खुला रहेगा, जिस पर उसकी अपनी योग्यता के आधार पर विचार किया जाना होगा, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया था कि उच्च न्यायालय ऐसा करेगा। स्थानीय स्थितियों पर विचार करने और पार्टियों पर लगाई जाने वाली शर्तों, यदि कोई हो, सहित अंतरिम आदेश पारित करने की बेहतर स्थिति में हो।

जैसा कि यहां पहले उल्लेख किया गया है, छुट्टी मंजूर होने पर एसएलपी को सिविल अपील संख्या 6626/04 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया था, जिसे अंतिम सुनवाई और निपटान के लिए हमारे द्वारा लिया गया है।

अपीलकर्ता, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ, ने आग्रह किया कि परिवार न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, नाबालिग बच्चे को मां की अभिरक्षा से पिता की अभिरक्षा में हटाकर कानूनी गलती की है। वह अभी भी कम उम्र की थी और उस उम्र में पहुँच गई थी जब एक माँ की देखभाल और परामर्श नाबालिग लड़की के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सर्वोपरि थी। अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि नाबालिग बच्ची जल्द ही युवावस्था प्राप्त कर लेगी जब उसे एक

महिला के मार्गदर्शन और निर्देशों की आवश्यकता होगी ताकि वह इस अवधि के दौरान होने वाले शारीरिक और भावनात्मक दोनों परिवर्तनों से निपटने में सक्षम हो सके।

उपरोक्त के अलावा, अपीलकर्ता, जो, जैसा कि यहां पहले कहा गया है, पेशे से एक डॉक्टर है, ने दावा किया कि वह उस प्रत्यर्थी की तुलना में नाबालिग की जरूरतों की देखभाल करने के लिए बेहतर स्थिति में है, जिस पर आरोप लगाया गया था। नाबालिग बच्चे की जरूरतों की देखभाल के लिए उसके पास बहुत कम समय था।

पक्षों की ओर से पेश किए गए सबूतों से अपीलकर्ता ने यह बताने की कोशिश की कि सुबह से देर रात तक प्रत्यर्थी अपने काम और गतिविधियों में अदालत में व्यस्त था, जिससे नाबालिग बच्चा पूरी तरह से अकेला और उपेक्षित हो गया। अपीलकर्ता के अनुसार, प्रत्यर्थी, जिसका त्रिशूर से कुछ दूरी पर एक फार्म हाउस था, अपने सप्ताहांत और यहां तक कि सप्ताह के दिनों का एक बड़ा हिस्सा उक्त फार्म हाउस में बिताता था। अपीलकर्ता ने आग्रह किया कि एक माँ के रूप में, वह जानती थी कि बच्चे के लिए सबसे अच्छा क्या हैं और एक पेशेवर व्यक्ति होने के नाते वह न केवल नाबालिग को ऐसी सभी सुविधाएँ प्रदान करने की स्थिति में थी जो उसके उचित और पूर्ण पालन-पोषण के लिए आवश्यक थीं, बल्कि अच्छी शिक्षा के साथ-साथ संगीत और नृत्य जैसी पाठ्येतर गतिविधियों में उसकी रुचि पैदा करना। अपीलकर्ता ने दृढ़तापूर्वक आग्रह किया कि प्रत्यर्थी को उसके जन्म के बाद से और उस समय तक जब अपीलकर्ता उसके साथ कालीकट के लिए रवाना हुआ, तब तक नाबालिग बच्चे के बारे में कभी कोई चिंता नहीं थी। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि नाबालिग बच्चे के जन्म के बाद 7 साल तक, अपीलकर्ता ने अकेले ही नाबालिग को पाला था क्योंकि प्रत्यर्थी अन्य गतिविधियों में इतना व्यस्त था कि उसे नोटिस भी नहीं किया गया था। अपीलकर्ता के अनुसार, जब तक प्रत्यर्थी ने नाबालिग की अभिरक्षा का दावा करना शुरू नहीं किया तब तक नाबालिग बच्चा उसके साथ रहकर बेहद खुश था और ऐसी अभिरक्षा प्राप्त

करने के तुरंत बाद, वह नाबालिग को इस हद तक प्रभावित करने में सक्षम हो गया कि वह इस हद तक पहुंच गई पारिवारिक न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश को सूचित करना कि वह अपने पिता के साथ रहना पसंद करती है।

मामले के इस पहलू पर, अपीलकर्ता ने आग्रह किया कि नाबालिग को प्रत्यर्थी द्वारा "माता-पिता अलगाव सिंड्रोम " के रूप में उजागर किया गया था। उन्होंने आग्रह किया कि ऐसी घटना उन माता-पिता में ध्यान देने योग्य है जो अलग हो चुके हैं और जो अपने नाबालिग बच्चों के दिमाग में दूसरे पक्ष के खिलाफ जहर भरने पर आमादा हैं। अपीलकर्ता के अनुसार, अन्यथा कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं हो सकता है कि 7 साल तक अपीलकर्ता के साथ रहने के बाद भी, नाबालिग बच्चे ने अपने पिता की अभिरक्षा में रखे जाने के बाद उसके साथ रहने की प्राथमिकता क्यों व्यक्त की थी। अपीलकर्ता ने अपनी दलीलों पर जोर दिया कि न केवल 8 साल की उम्र तक, जब नाबालिग बच्चे की कस्टडी उसे दी गई थी, बल्कि उसके बाद भी प्रत्यर्थी एक अनुपस्थित पिता था और मामलों और पालन-पोषण में बहुत कम या कोई दिलचस्पी नहीं लेता था। नाबालिग बच्चे का अपीलकर्ता के अनुसार, प्रत्यर्थी की अजीब आदतों को देखते हुए, नाबालिग बच्ची को ज्यादातर समय उसके अकेले छोड़ दिया जाता था, जो एक बढ़ती हुई किशोर लड़की के लिए न तो वांछनीय था और न ही स्वस्थ ।

यह आग्रह करते हुए कि उसके दिल में नाबालिग बच्चे का सर्वोत्तम हित है, अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि हिंदू कानून के प्रावधानों के तहत, जिसके द्वारा पार्टियां शासित होती हैं, पिता को नाबालिग के प्राकृतिक अभिभावक के रूप में स्वीकार किया जाता है, ऐसे कई उदाहरण हैं जहां अदालतों ने नाबालिग के उपलब्ध होने पर भी पिता के बजाय मां को उसके प्राकृतिक संरक्षक के रूप में स्वीकार किया था। हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6 का संदर्भ देते हुए, जो प्रावधान करता है कि लड़के या अविवाहित लड़की के मामले में हिंदू नाबालिग का

प्राकृतिक संरक्षक पिता है और उसके बाद मां है; बशर्ते कि 5 वर्ष की आयु पूरी न करने वाले नाबालिग की अभिरक्षा आम तौर पर मां के पास होगी, अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त प्रावधान ने मां को भी नाबालिग के प्राकृतिक अभिभावक के रूप में मान्यता दी है। यह आग्रह किया गया था कि विभिन्न मामलों में न्यायालयों ने उक्त प्रावधान पर विचार किया था और राय दी थी कि ऐसे मामले हो सकते हैं जहां पिता के उपलब्ध होने के बावजूद, उसकी अक्षमता को ध्यान में रखते हुए मां को नाबालिग का प्राकृतिक संरक्षक माना जाना चाहिए। पिता को ऐसे नाबालिग के प्राकृतिक संरक्षक के रूप में कार्य करना होगा।

अपने पूर्वोक्त निवेदन के समर्थन में, अपीलकर्ता ने इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया और उस पर भरोसा किया। होशी शवाक्ष डोलिकुका बनाम थ्रिटी होशी डोलिकुका, जिसमें नाबालिग के पिता को बच्चे के कल्याण के प्रति उदासीन पाते हुए इस न्यायालय ने माना कि पिता बच्चे की अभिरक्षा का हकदार नहीं है।

अपीलकर्ता ने मामले में केरल उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले का भी हवाला दिया और उस पर भरोसा किया। कुरियन सी जोस बनाम मीना जोस, जिसमें इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पिता एक उपपत्नी के साथ रह रहा था, जो कोई और नहीं बल्कि माँ की सबसे छोटी बहन थी, यह माना गया कि पिता नाबालिग के संरक्षक के रूप में कार्य करने का हकदार नहीं था। संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 17(3) के प्रावधानों पर विचार करने पर, यह भी माना गया कि एक नाबालिग की प्राथमिकता आवश्यक रूप से निर्णायक नहीं है, बल्कि अदालत द्वारा विचार किए जाने वाले कारकों में से केवल एक है। अभिरक्षा के सवाल पर विचार।

थाकुमार वी. जाहगीरदार बनाम. चेतना रामतीर्थ के मामले में इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय का भी संदर्भ दिया गया, जिसमें नाबालिग बच्चे के हित को ध्यान में

रखते हुए, उस मां को, जिसने दोबारा शादी की थी, उस बच्ची की कस्टडी दी गई, जो युवावस्था के आगमन पर थी, इस आधार पर कि ऐसी उम्र में एक बच्ची को मुख्य रूप से एक की आवश्यकता होती है। माँ की देखभाल और ध्यान न्यायालय का विचार था कि पिता के घर में महिला कंपनी की अनुपस्थिति नाबालिग महिला बच्चे की अभिरक्षा देने का निर्णय लेने में एक प्रासंगिक कारक थी।

अपीलकर्ता ने आग्रह किया कि उपरोक्त मामलों में अदालतों ने अभिरक्षा देने के सवाल पर निर्णय लेने में नाबालिग के कल्याण को सर्वोपरि माना है। अपीलकर्ता ने आग्रह किया कि इस तथ्य के बावजूद कि नाबालिग बच्ची ने फैमिली कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश के समक्ष व्यक्त किया था कि वह पिता के साथ रहना पसंद करती है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नाबालिग का कल्याण सर्वोपरि है, अदालत को गंभीरता से लेना चाहिए। इस बात पर विचार करें कि क्या किशोरावस्था के दौरान नाबालिग बच्चे को उसकी माँ के साथ से वंचित किया जाना चाहिए जब उसे अपनी माँ के परामर्श और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि जबकि प्रत्यर्थी ने ऋत्विका का स्नेह पाने के लिए उसे अपने साथ जोड़ लिया था, अपीलकर्ता ने उसके मन में अनुशासन की भावना पैदा करने की कोशिश की थी, जिससे स्पष्ट रूप से ऋत्विका में कुछ हद तक नाराजगी पैदा हुई थी। अपीलकर्ता ने कहा कि अदालत को यह देखने के लिए पर्दे के पीछे देखना चाहिए कि बड़े होने के इस महत्वपूर्ण समय में नाबालिग लड़की के लिए सबसे अच्छा क्या था।

अपने पूर्वोक्त निवेदन के समर्थन में, अपीलकर्ता ने मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला दिया और उस पर भरोसा किया। सरस्वतीबाई श्रीपाद वेद बनाम श्रीपाद वासनजी वेद, जिसमें संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम के तहत एक समान आवेदन में, यह माना गया था कि चूंकि नाबालिग का हित सर्वोपरि है, इसलिए अभिभावक के रूप में पिता की तुलना में मां को प्राथमिकता दी जाती हैं। अपीलकर्ता ने

फैसले में की गई टिप्पणी पर जोर दिया कि यदि मां बच्चे की देखभाल करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति है, तो इस तथ्य के बावजूद कि कम उम्र के बच्चे की देखभाल के लिए उसके लिए पर्याप्त विकल्प ढूंढना काफी असंभव है। नाबालिग का प्राकृतिक संरक्षक बना रहता है।

इसी तरह का विचार इस न्यायालय द्वारा के मामले में व्यक्त किया गया थारोजी जैकब बनाम जैकब ए. चक्रमक्कल, जिसमें मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, बेटी (भले ही वह 13 वर्ष से अधिक उम्र की थी) और सबसे छोटे नाबालिग बेटे की कस्टडी को पति के बजाय पत्नी के साथ अधिक फायदेमंद माना गया था।

अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि बच्चे के बढ़ते वर्षों के दौरान, उसने अपनी व्यावसायिक आय से उसे वह सुविधाएँ प्रदान कीं जिनकी एक बढ़ते बच्चे को आवश्यकता होती है, जिसमें एक अच्छे स्कूल में बच्चे की स्कूली शिक्षा के लिए प्रवेश और ट्यूशन फीस और पाठ्येतर के लिए ट्यूशन फीस शामिल थी। गतिविधियाँ । अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उसने नाबालिग के लाभ के लिए सावधि जमा की थी और यहां तक कि जीवन बीमा पॉलिसी भी ली थी जिसमें नाबालिग बच्चे को नामांकित किया गया था। अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त के अलावा, उसने नाबालिग के लाभ के लिए विभिन्न वित्तीय निवेश भी किए थे ताकि अगर उसे अपीलकर्ता के साथ रहने की अनुमति दी जाए तो नाबालिग बच्चे को किसी भी चीज़ की कमी न हो।

अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि उसे विभिन्न अंतरिम आदेशों द्वारा मुलाकात का अधिकार दिया गया था, क्योंकि वह कालीकट में रह रही थी और प्रत्यर्थी त्रिशूर में रह रहा था, वह बीच की दूरी के कारण अपनी नाबालिग बेटी के संपर्क में रहने में असमर्थ थी । कालीकट और त्रिशूर. दरअसल, अपीलकर्ता ने इस तथ्य की शिकायत की थी कि कई मौकों पर जब वह प्रत्यर्थी के आवास पर अपने नाबालिग

बच्चे से मिलने गई थी, तो उसे बच्चे से मिलने या उसके साथ पर्याप्त समय बिताने की अनुमति नहीं दी गई थी। अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि यदि नाबालिग बच्ची की अभिरक्षा अपीलकर्ता को दे दी जाए तो उसके हित की सबसे अच्छी सेवा होगी।

अपीलकर्ता द्वारा किए गए नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा के दावे का प्रत्यर्थी ने बहुत दृढ़ता से विरोध किया, जिसने नाबालिग और उसके विकास के प्रति उसकी कथित उदासीनता के संबंध में उसके खिलाफ लगाए गए सभी विभिन्न आरोपों से इनकार किया। उनकी ओर से दलील दी गई कि 7 साल की उम्र तक बच्चा माता-पिता दोनों के साथ रहा था और इस दौरान उसकी अच्छी तरह से देखभाल की गई थी। अपीलकर्ता द्वारा नाबालिग बच्चे को अचानक और गुप्त रूप से प्रत्यर्थी की अभिरक्षा से हटा दिया गया था, जिसने 26 फरवरी, 2000 को अपीलकर्ता को सूचित किए बिना अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया था, जो अपने पेशेवर काम पर त्रिशूर से बाहर गया था। यह प्रस्तुत किया गया कि केवल यह जानने के बाद कि अपीलकर्ता ने बच्चे को कालीकट ले जाया है, प्रत्यर्थी को केरल उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो अपीलकर्ता द्वारा नाबालिग बच्चे को त्रिशूर लाने के लिए दिए गए वचन पर समाप्त हुई। इसके बाद ही प्रत्यर्थी को संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम की धारा 7 और 25 और हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6 के तहत आवेदन दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

प्रत्यर्थी के अनुसार, भले ही अपीलकर्ता ने नाबालिग को जबरन कालीकट ले जाया था, जिससे प्रत्यर्थी को नाबालिग बच्चे की कंपनी से वंचित होना पड़ा, त्रिशूर में फैमिली कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश द्वारा अपने साक्षात्कार के दौरान उक्त नाबालिग ने अपनी पसंद बताई विद्वान न्यायाधीश के परिचित पिता के साथ।

प्रत्यर्थी की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बालिका युवावस्था की आयु प्राप्त कर रही थी, प्रत्यर्थी ने अपनी बड़ी बहन, जो एक स्कूल की सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापिका थी, के साथ आने की व्यवस्था की थी। उसके साथ रहें और बढ़ते वर्षों के दौरान नाबालिग की ज़रूरतों पर ध्यान दें जब उसे एक महिला के मार्गदर्शन और परामर्श की आवश्यकता होती है। यह प्रस्तुत किया गया कि मामले के उक्त पहलू पर परिवार न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी की बहन द्वारा नाबालिग बच्चे की देखभाल के लिए प्रत्यर्थी के साथ रहने की इच्छा व्यक्त करने वाले एक हलफनामे के आधार पर विधिवत विचार किया गया था।

उपरोक्त के अलावा, प्रत्यर्थी की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि अदालत ने साक्ष्य के आधार पर पाया था कि उसके पास नाबालिग बच्चे की देखभाल और सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन था। किसी भी घटना में, सबसे महत्वपूर्ण बात नाबालिग का कल्याण था और अदालत ने संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 17(3) के संदर्भ में नाबालिग द्वारा व्यक्त की गई प्राथमिकता को भी ध्यान में रखा था।

प्रत्यर्थी की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि प्रत्यर्थी इस तथ्य से पूरी तरह सहमत है कि नाबालिग बच्चे को उसकी मां की कंपनी से वंचित नहीं किया जाना चाहिए और उक्त उद्देश्य के लिए, अपीलकर्ता का नाबालिग बच्चे से मिलने के लिए स्वागत है। प्रत्यर्थी के घर या किसी तटस्थ स्थान पर और यहां तक कि यदि वह अपीलकर्ता के साथ रहने के लिए तैयार और इच्छुक हो तो निर्दिष्ट दिनों में बच्चे को अपने साथ रख सकती है । प्रत्यर्थी की ओर से जिस बात पर जोर देने की मांग की गई थी, वह यह थी कि बच्चे के हित में उसे उसके साथ रहने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि वह नाबालिग की देखभाल करने के अलावा, उसका प्राकृतिक अभिभावक

होने और इच्छाओं का भी ध्यान रखने के लिए बेहतर रूप से सुसज्जित था। खुद नाबालिग की।

उस स्थिति की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए जिसमें हमें नाबालिग बच्चे के माता-पिता के भावनात्मक टकराव और नाबालिग के कल्याण को संतुलित करने के लिए कहा गया है, हमने इस बात पर उत्सुकता से विचार किया है कि बच्चे के सर्वोत्तम हित में क्या होगा नाबालिग हमने इस मामले में उसकी पसंद का पता लगाने के लिए, माता-पिता में से किसी की उपस्थिति के बिना, खुद ही नाबालिग लड़की से बात की है। 12 वर्ष से कुछ अधिक उम्र की बच्ची अत्यधिक बुद्धिमान है, उसने स्कूल में अपनी पढ़ाई में लगातार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और हमें विश्वास था कि उसके माता-पिता के बीच झगड़े के बावजूद, वह एक बुद्धिमान विकल्प चुनने की स्थिति में होगी। उसकी अभिरक्षा के संबंध में नाबालिग के साथ हमारी चर्चा से, हम यह समझने में सक्षम हुए हैं कि यद्यपि उसकी अपनी माँ के प्रति कोई शत्रुता नहीं है, फिर भी वह उस पिता के साथ रहना पसंद करेगी जिसके साथ वह अधिक सहज महसूस करती है। नाबालिग बच्ची ने हमें यह भी बताया कि उसने अपनी मौसी के साथ बहुत अच्छे संबंध स्थापित कर लिए हैं, जो अब उसके पिता के घर में रह रही थी और वह अपनी मौसी से उन मामलों में भी संबंध बनाने में सक्षम थी जो किशोरावस्था के दौरान एक बढ़ती लड़की के लिए चिंता का विषय हो सकते थे।

हमने अपीलकर्ता द्वारा उद्धृत विभिन्न निर्णयों पर भी विचार किया है जो प्रत्येक मामले के विशेष तथ्यों में दिए गए थे। उक्त मामलों में पिता को विशिष्ट कारणों से नाबालिग के संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए उपयुक्त नहीं माना गया। न्यायालयों द्वारा उक्त निर्णय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दिए गए थे कि ऐसे मामलों में सर्वोपरि विचार नाबालिग का हित और कल्याण था। इस मामले में, हमें प्रत्यर्थी को नाबालिग की देखभाल के लिए अयोग्य मानने का कोई कारण नहीं दिखता। वास्तव में,

नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा प्राप्त करने के बाद, ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि प्रत्यर्थी ने नाबालिग की उपेक्षा की है या उसकी सभी जरूरतों की देखभाल की है। ऐसा लगता है कि बच्चा प्रत्यर्थी की संगति में खुश है और स्कूल में भी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। प्रत्यर्थी आर्थिक रूप से स्थिर प्रतीत होता है और वह किसी भी तरह से नाबालिग बच्चे का अभिभावक बनने के लिए अयोग्य नहीं है। अपीलकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी के खिलाफ नाबालिग के प्रति उसकी कथित उदासीनता के अलावा कोई आरोप नहीं लगाया गया है। इस तरह का आरोप हमारे सामने मौजूद सामग्रियों से सामने नहीं आया है और यह प्रत्यर्थी को नाबालिग के अभिभावक के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

इसलिए, हम महसूस करते हैं कि नाबालिग के हित की सबसे अच्छी सेवा होगी यदि वह प्रत्यर्थी के साथ रहे, लेकिन अपीलकर्ता के पास लगातार अंतराल पर नाबालिग से मिलने के लिए पर्याप्त पहुंच हो, ताकि उसकी सामान्य पढ़ाई और अन्य चीजों में बाधा न आए। गतिविधियाँ। तदनुसार, हम अभिभावक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 7 और 25 के तहत प्रत्यर्थी द्वारा दायर ओपी नंबर 193/2000 का निपटारा करते हुए 20.3.2001 को त्रिशूर में पारिवारिक न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए इस अपील का निपटान करते हैं। निम्नलिखित संशोधनों के साथ:

1. प्रत्यर्थी ऋत्विका के लिए उसके वर्तमान स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी रखने की व्यवस्था करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वह पाठ्येतर गतिविधियों में भी भाग लेने में सक्षम हो।

2. प्रत्यर्थी को नाबालिग की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, भोजन और कपड़े के सभी खर्चों को पूरा करना होगा और यदि अपीलकर्ता बच्चे के पालन-पोषण में भी

योगदान देना चाहती है, तो प्रत्यर्थी इसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा और अपीलकर्ता को भी ऐसा योगदान करने से रोकेगा।

3. अपीलकर्ता महीने के हर दूसरे रविवार को सहमति के अनुसार प्रत्यर्थी के घर या किसी पारस्परिक मित्र के परिसर में नाबालिग बच्चे से मिलने के लिए स्वतंत्र होगी। अपीलकर्ता को बच्चे से मिलने में सक्षम बनाने के लिए, प्रत्यर्थी को सुबह 10.00 बजे अपने घर में या पारस्परिक मित्र के घर में बच्चे की उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी, अपीलकर्ता उस दिन बच्चे को अपने साथ बाहर ले जाने की हकदार होगी, और उसे प्रत्यर्थी के घर या पारस्परिक मित्र के परिसर में शाम 7.00 बजे के भीतर वापस लाने के लिए।

4. यदि अपीलकर्ता अपना निवास स्थान उसी शहर में स्थानांतरित करती है जहां नाबालिग बच्चा रहेगा, तो उपरोक्त के अलावा, अपीलकर्ता महीने के हर दूसरे शनिवार को नाबालिग से मिलने की हकदार होगी, और यदि यदि बच्चा इच्छुक है, तो अपीलकर्ता ऐसे शनिवार को रात भर बच्चे को अपने पास रखने और अगले रविवार शाम 7.00 बजे तक उसे प्रत्यर्थी की अभिरक्षा में वापस करने की भी हकदार होगी।

5. अपीलकर्ता, प्रत्यर्थी को पूर्व सूचना देने पर, सप्ताह में एक बार स्कूल समय के बाद लगभग एक घंटे के लिए नाबालिग से उसके स्कूल में मिलने की भी हकदार होगी।

6. अपीलकर्ता पार्टियों के बीच पारस्परिक रूप से तय की जाने वाली तारीखों पर गर्मी की छुट्टियों के दौरान लगातार 10 दिनों तक नाबालिग की अभिरक्षा की भी हकदार होगी।

7. उपरोक्त व्यवस्था फिलहाल जारी रहेगी, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों के कारण आवश्यक होने पर पक्ष नए निर्देशों के लिए त्रिशूर में फैमिली कोर्ट से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

प्रत्येक पक्ष अपना खर्च स्वयं वहन करेगा।

अपील निस्तारित

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमती सोनिया गौरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।